ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-129-133**,YEAR-2015

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ

❑ **डॉ0 ममता मणि त्रिपाठी**

सारांश– *डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम मोदी सरकार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी छतरी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण किये जाने की योजना है। हर गाँव कस्बा पंचायत और शहर को ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की मुहिम। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन थमाने की कोशिश जो परियोजना के डिलीवरी प्रणाली का आधार बनेगा। 1.13 लाख करोड़ की इस महत्वाकाँक्षी योजना के मूर्त रुप लेने के बाद देश का कोई नागरिक कहीं से भी किसी प्रकार की सरकारी सेवा सहजता से ले सकेगा, बहुआयामी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली इस योजना से देश की पूरी कार्य संस्कृति बदलने का इरादा है। तकनीक के सहारे लोगों के भविश्य को तराशते हुए देश की अर्थव्यवस्था को तेज करना भी इसके निहितार्थों में एक है। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम योग्यता एवं तकनीक के इस्तेमाल से समावेशी एवं टिकाऊ वृद्धि से भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रुप से सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलते हुए आई0टी0 (Indian Talent) vkbZ0Vh0 (Information Technology) आई0टी0 (Indian Tomorrow) को प्राप्त कर परिवर्तनकारी बनाना है। इसका उद्देश्य युवा भारत की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ युग्मित प्रौद्योगिकी के लिए भारत को सशक्त क्षमता निर्माण के लिए विकल्प एवं दिशा देना है। डिजिटल इण्डिया को डिजिटली और डिजिटल से वंचित गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, रोजगार एवं बेरोजगार, साक्षर एवं निरक्षर और सशक्त एवं अशक्त के बीच खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को सशक्त सूचना समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रुपांतरित करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और साधन तैयार करना जिससे लोगों को इलेक्ट्रानिक रुप से सेवायें मिल सके तथा साथ ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल सके।*

डिजिटल इण्डिया के तहत केन्द्र सरकार 3 बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है–

1. देश में व्यापक स्तर पर आधारभूत डिजिटल सेवाओं का विकास जिनका प्रयोग नागरिकों द्वारा बेरोकटोक किया जा सके।

2. जनता को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से सरकारी सेवायें एवं प्रशासनिक सुविधाएँ हर समय उपलब्ध हों जिसे तकनीकी भाषा में ondemand कहते हैं।

3. भारतीय नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम एवं सबल बनाना इसके लिए जरुरी है कि तकनीकी उपकरणों, सुविधाओं, ज्ञान एवं सूचनाओं को समाज के सभी स्तरों तक पहुँचाया जाए।

आज दुनिया भर में आबादी को इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग बेवसाइट फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरवर्ग ने पिछले दिनों अपने भारत दौरे के समय कहा था कि भारत के 23 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं जबकि एक अरब आज भी इससे वंचित हैं। यदि भारत अपने गाँवों को तकनीक से जोड़ने में सफल रहता है तो दुनिया उसकी ओर ध्यान देने पर मजबूर होगी। 28 फरवरी 2015 के ऑकड़ों को देखा जाए तो देश में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या के हिसाब से यह ऑकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत

विभागाध्यक्ष (राजनीति शास्त्र), श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज,पावानगर फाजिलनगर कुशीनगर, (उ0प्र0) भारत

चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि स्मार्टफोन की बात की जाए तो देश में वर्ष 2013 में गूगल के आवर मोबाइल लेनेट नें स्मार्टफोन की पहुँच को लेकर विभिन्न देशों की एक सूची जारी की जिसमें भारत 16.8 प्रतिशत के साथ 45वें स्थान पर था। सही मायने में डिजिटल इण्डिया के उद्देश्यों की पूर्ति इसी क्रांति के माध्यम से हो सकती है।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल है इसके लिए प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सेवा मुहैया कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जायेगा। ऐसी बुनियादी सुविधाओं के बूते देश ज्ञान के एक ऐसे भविष्य की ओर उन्मुख होगा जहाँ प्रशासन एवं सेवा हर माँग पर उपलब्ध होगी। ऐसे में प्रशासन की जबावदेही और पारदर्शिता का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना भी अर्थव्यवस्था के लिए अहम मुद्दा है इसी सोच के साथ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र आधार कार्ड को भी डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। यह संख्या भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति की पहचान एव पते का निर्धारण करती है आधार संख्या से उन्हें बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी गैर सरकारी सेवाओं की सुविधाएँ प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पहल योजना के अन्तर्गत गैस सब्सिडी जैसे अनुदान सीधे ही उपभोक्ताओं के बैंक खाते में पहुँच रहे हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017 तक 2.5 लाख गाँवों में ब्राडबैंड इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लगभग इतने ही विद्यालयों को वर्ष 2019 तक वाई फाई सुविधा से लैस कर दिया जायेगा। डिजिटल सेवाओं के सार्थक प्रयोग के लिए डिजिटल शिक्षा तथा जागरुकता महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार का 'दिशा' नामक कार्यक्रम इसमें हाथ बढ़ायेगा और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को डिजिटल साक्षरता की तरफ ले जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि आई0टी0 भरत को वैसे ही जोड़ती है जैसे रेलवे देश को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इण्डिया हमें दुनिया का मुकाबला करने में सक्षम बनायेगा। डिजिटल इण्डिया में हर गाँव ब्राडबैंड से जुड़ जायेंगे इससे ऑनलाइन लेक्चर यानी स्कूल कालेज में पढ़ाई, टेलिमेडिसन यानी सरकारी सहायता पहुँचाने की बात कही गयी है। खोजी बेवसाइट विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन पॉल असेंजे ने जब इराक युद्ध से जुड़े लगभग 40 लाख दस्तावेज अपनी बेवसाइट पर जारी किये तो दुनिया भर में सनसनी फैल गयी थी। इसमें अमेरिका, इंग्लैण्ड एवं नाटो की सेनाओं पर गंभीर अपराध करने के सबूत मिले थे। जिमीवेल्स इंटरनेट पर मौजूद इनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया के संस्थापक और प्रमोटर हैं। जब अमेरिका के इंटरनेट पायरेसी कानून का विरोध करने के लिए विकीपीडिया ने 24 घण्टे तक अपना संचालन बन्द रखा तो यह दुनिया भर में मौजूद तमाम Internet यूजर्स की परेशानी का मुख्य वजह बन गयी।

डिजिटल इण्डिया के 9 स्तम्भ हैं :

1. **ब्राडबैंड हाइवे**– इन्टरनेट का विस्तार देश के विकास को रतार देगा। इसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क देश में ई–कामर्स के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। इस परियोजना के तहत साल 2017 तक देश के ढाई लाख गाँवों में हाईस्पीड ब्राडबैंड इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिये गाँवों को इंटरनेट सुपरहाइवे से समृद्ध किया जाए। यह नेटवर्क ई–कामर्स की क्रांति लाने में भी मददगार साबित होगा। जब इंटरनेट देश के सभी शहरों और गाँवों में पहुँच जायेगा तो लोग ऑनलाइन शापिंग के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे देश में ई–कामर्स का विस्तार होगा। भंडारण की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी इससे न केवल नौकरियों के ज्यादा मौके उपलब्ध होंगे बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता भी खुलेगा। ग्लोबल फर्म PWC और उद्योग चैंबर एसोचेम के साझा अध्ययन के मुताबिक साल 2017 से 2020 तक देश में ई–रिटेल उद्योग का आकार 10 से 20 अरब डॉलर 60,000 से 1,20,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगा।

2. **सभी के हाथ में मोबाइल**–इस कार्यक्रम का आधार मोबाइल होगा। इसके माध्यम से ही सारी जरुरतें जानकारियाँ और जबाबदेही तय की जायेगी

लिहाजा सभी नागरिकों तक मोबाइल की पहुँच का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018 रखा गया है इस अवधि तक देश के सभी ग्रामीणों के हाथ मोबाइल पहुँच चुका होगा इसमें करीब 16 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम– वर्ष 2017 तक देश की 2.5 लाख पंचायतों में एक आम सेवा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। 1.5 लाख डाकघर भी इससे जुड़ी कई सेवायें मुहैया करायेंगे। इसमें करीब 4750 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

4. ई0गवर्नेंस– तकनीक के इस्तेमाल में सरकार और उसकी कार्य संस्कृति को संवारने की मंशा के तहत हर तरीके के प्रमाण–पत्र को आनलाइन मुहैया कराने की कोशिश होगी। हर नागरिक की एक विशिष्ट पहचान होगी इसके अलावा इससे जुड़े अन्य प्रपत्रों एवं सूचनाओं पर एक ऑनलाइन संग्रह होगा। सरकार के विभिन्न विभाग इन प्रपत्रों एवं सूचनाओं को देख व समझ सकेंगे। कई तरह की सेवाओं, आधार पेमेण्ट गेटवे जैसी और मंचों को एकीकृत किया जायेगा। सरकार की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं ऑटोमोड में लाने की कोशिश होगी। जन शिकायतों का त्वरित निपटारा होगा।

5. ई0क्रांति– इसके तहत सभी सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सुनिश्चित होगी। ब्राडबैंड के माध यम से ई–एजुकेशन, ई–हेल्थकेयर जेसे कार्यक्रमों का लोग लाभ उठा सकेंगे। वाई फाई सुविधा मुत होगी। ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराये जायेंगे। ऑनलाइन सलाह, रिकार्डों की आपूर्ति होगी। किसानों को खेती की जानकारियाँ ऑनलाइन मिलेगी। सबका वित्तीय समावेश किया जायेगा। ई–कोर्ट, ई–पुलिस आदि की सुविधा।

6. सभी के लिए सूचना – सूचनाएँ और प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार लोगों से जुड़ी होगी इसके लिए बहुत अल्प संख्या में संसाधनों की जरुरत होगी।

7. इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग– इस समग्र कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्माण में देश का आत्मनिर्भर बनना जरुरी है अभी पेट्रोलियम पदार्थों और सोनें के आयात में सर्वाधिक धन खर्च करने के बाद तीसरा नम्बर इन्हीं इलेक्ट्रानिक उपकरणों का आता है। इसके लिए सेमीकंडक्टर अत्पादों को मदद दिये जाने की जरुरत है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के शून्य आयात के लक्ष्य को पाया जा सके।

8. आई टी में रोजगार सृजन– अगले पाँच साल के दौरान कस्बों और गाँवों के एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसी अवधि के दौरान पाँच लाख ग्रामीण आईटी कार्यशक्ति तैयार करने का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर के हर राज्यों में वी0पी0ओ0 की सुविधा होगी।

9. उत्पादकता में वृद्धि – संसाधनों के पूरे इस्तेमाल पर जोर होगा। सभी सरकारी महकमों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा। सभी विश्वविद्यालय वाई फाई से लैस होंगे। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हॉट स्पॉट विकसित किये जायेंगे।

डिजिटल इण्डिया के लिए निर्धारित वर्ष 2019 की समय सीमा बहुत दूर नही है जो इतनी विशाल परियोजना के लिए बड़ी चुनौती सिद्ध होने वाली है भारत में बिजली, आधारभूत सुविधाओं, संचार तंत्र की सीमाएँ हैं। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सेवाएँ मुहैया कराने के लिए विशाल तंत्र के निर्माण की जरुरत है और उसे स्थायित्व देने के लिहाज से लाभप्रद बनाए जाने की भी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सेवाएँ मुहैया कराने के लिए विशाल तंत्र के निर्माण की जरुरत है और उसे स्थायित्व देने के लिहाज से लाभप्रद बनाए जाने की भी।

➲ डिजिटल इण्डिया के संदर्भ में अनेक चुनौतियों का जिक्र किया जा रहा है जैसे डिजिटल साक्षरता का अभाव, गाँव कस्बों में कम्प्यूटरों की संख्या के कमजोर ऑकड़े ब्राड बैंड, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमजोर रफ्तार आदि। गाँव कस्बों तक ई गवर्नेंस के लाभ पहुँचानें के संदर्भ में केवल तकनीकी सीमाएँ नही हैं हमारी अन्य सीमाएँ भी उस लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट पैदा कर सकती है जैसे– बिजली की समस्या, जिसके बिना गाँव देहात के लोगों का सरकारी

ई प्रणालियों के साथ सम्पर्क कर पाना दिक्कत तलब होगा।

➲ एक अन्य चुनौती मानव संसाधन की कमी है देश में जितना मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है उसे कई गुना बढ़ाने की जरुरत है। नेसकाम के मुखिया आर चन्द्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढ़ाई लाख पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रुप से प्रभावित हो सकती है।

➲ तीसरी बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की है। केन्द्र सरकार का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर इससे विशाल कार्यक्रम पहले कभी नही चलाया गया।

➲ चौथी बड़ी चुनौती गाँवों के साथ–साथ शहरों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाना।

➲ पाँचवी बड़ी चुनौती अंग्रेजी के अलावा कम्यूनिकेशन जैसी साट स्किल्स विकसित करना है।

➲ हर पंचायत के स्तर पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाना बड़ी चुनौती है।

➲ गाँवों में युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण देना भी एक चुनौती है।

➲ विद्युत सामानों का उत्पादन सिर्फ शहरों तक सीमित किया जाना चाहिए।

किन्तु सभी समस्याओं का समाधान असंभव नही है और प्रधानमंत्री को इन चुनौतियों का बखूबी अहसास दिखता है दूसरे समय उनके साथ है। जनहित में सूचना तकनीक और दूरसंचार क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प उन्होंने लिया है उसके लिए संभवतः यह सर्वाधिक अनुकूल समय है। पहला देश में आधी से अधिक संख्या 35 वर्ष के आयु के युवाओं की है जो तकनीक के प्रति स्वाभाविक लगाव रखते हैं और उसे दिलचस्पी से देखते और प्रयोग करते हैं। दूसरे देश में मोबाइल फोन, इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। बी0आर0सोशल की डिजिटल सोशल एण्ड मोबाइल 2015 के सर्वे के अनुसार : एक भारतीय औसतन 5 घण्टे 4 मिनट कम्प्यूटर, टेबलेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर 1 घण्टा 58 मिनट तथा सोशल मीडिया पर 2 घण्टे 31 मिनट का समय देते हैं। मोबाइल इंटरनेट पर औसत 2 घण्टे 24 मिनट तक कार्य करते हैं। भारत में 24.3 करोड़ लोग इंटरनेट पर सक्रिय है तथा 11.8 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। 2018 तक 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हो जायेंगे। भारतीय साटवेयर और आई0टी0 सेवाओं के शीर्ष नैसकाम ने जिस अंदाज से मोदी की घोषणाओं का स्वागत किया वह दिखाता है कि डिजिटल भारत और ई–गवर्नेंस के उनके विजन में कितनी कारोबारी और विकासात्मक संभावनाएँ छिपी हुई है। परियोजना की व्यापकता और विशालता के मद्देनजर सरकार को नये सहयोगियों के साथ जुड़ने में आपत्ति नही है। सरकार न सिर्फ आम लोगों, विशेषज्ञों आदि को जोड़ने की इच्छुक है बल्कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों को साथ लेकर चलने में भी कोई हिचक नही है। डिजिटल इण्डिया में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और यही वजह है कि गुगल, माइक्रोसाट, फेसबुक, अमेजन जैसी विश्व की अग्रणी आईटी कम्पनियों के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले दिनों भारत का दौरा किया है। आईबीएम और सिस्को जैसी अन्य कंपनिया भी परियोजना में अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। भारत के आईटी उद्योग के लिए भी बड़ा कारोबारी अवसर उभरनें जा रहा है।

इस तरह राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए सामाजिक उत्थान की योजना में समाज के निर्बल तथा अपवर्जित लोगों की आशाओं को उड़ान देती है। यदि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले तो आदर्श राष्ट्र की स्थिति दिखायी देगी। सरकारी तंत्र की जबाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरुरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा। यह कार्यक्रम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रयास होगा जहाँ सरकार और उसकी सेवाएँ नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हो और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान

करे। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को इस्तेमाल कर भारत को डिजिटल रुप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Suresh K. Chauhan, T.A.V. Murthy, 'Digital divide and India' (PDF) Shodhganga@INFLIBNET centre Retrived 20 June 2012
2. डंगडाल एस (2013) इंटरनेट एक्टिविज्म मिशिगनगेल ग्रुप
3. सिद्दिकी, एच(2010) इनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इन द इंटरनेट एज, नई दिल्ली अनमोल पब्लिकेशन
4. हिन्दुस्तान टाइम्स (2014, अप्रैल 24): hppt// www.hindustantimes. com/eiedions 2014 election-beat/digital democracy-who is winning-war-for votes on-twitter/article 1-121998aspx
5. hppt//en.wikipedia-org/wiki/list of countries-by smartphone penetration
6. योजना, प्रौद्योगिक नवाचार एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था, डिजिटल डेमोक्रेसी और नवाचार– उमाकांत मिश्र, नवम्बर 2014
7. 'योजना' संघीय ढाँचा और भारतीय राजनीति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रमः लोक प्रशासन सुधार की एक अनुकरणीय पहल नृपेन्द्र पी. राणा ऐटोनिस सी. सिमिन्टिरस फरवरी 2015
8. योजना समावेशी विकास एवं सामाजिक परिवर्तन डिजिटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश आशीष खंडेलवाल अगस्त 2015
9. कुरुक्षेत्र डिजिटल इण्डिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर– बालेन्दु शर्मा दधीचि दिसम्बर 2014
10. कुरुक्षेत्र डिजिटल इंडिया :परिकल्पना और चुनौतियाँ– सुनीता चौधरी अगस्त 2015
11. दैनिक जागरण 31 अगस्त 2014
12. दैनिक जागरण 5 जुलाई 2015

*****